भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 707

उत्तर देने की तारीख 08 दिसम्बर, 2023

हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा

707. श्री नीरज डांगी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करने के काम में तेजी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के उन राज्यों और जिलों का ब्यौरा क्या है जहां इंटरनेट सुविधाओं की पहुंच बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है;

(घ) देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ङ) राजस्थान में पिछले 10 वर्षों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। बेस ट्रांस-रिसीवर स्टेशन (बीटीएस) की संख्या मार्च, 2014 में 30,963 से बढ़कर नवंबर, 2023 में 1,59,399 हो गई है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 2014 में लगभग 1.25 करोड़ से बढ़कर सितंबर, 2023 में लगभग 5.06 करोड़ हो गई है। बेतार उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2014 में लगभग 5.27 करोड़ से बढ़कर जून, 2023 में लगभग 6.38 करोड़ हो गई है। टावरों की संख्या दिसंबर, 2015 में 17,592 से बढ़कर नवबंर, 2023 में 42,926 हो गई है। साथ ही राजस्थान में वर्ष 2014 तक बिछाई गई 69,260 किलोमीटर (कि.मी) ऑप्टिकल फाइबर की तुलना में सितंबर, 2023 तक 2,19,404 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा

चुकी है। नवबंर, 2023 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में 22,875 5जी बीटीएस संस्थापित किए जा चुके हैं।

राजस्थान राज्य/जिलों में कनेक्टविटी उपलब्ध कराने के लिए कुल 292 अभिगम और इंटरनेट सेवा लाइसेंस दिए गए हैं। अभिगम और इंटरनेट सेवा लाइसेंसधारकों की सूची विभागीय वेबसाइट https://dot.gov.in/data-services/2574 और https://dot.gov.in/unified-licencing पर उपलब्ध है।

सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(I) पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने, नकद निवेश करने, निवेश को बढ़ावा देने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर विनियामक बोझ को कम करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए विभिन्न संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों के कारण दूरसंचार क्षेत्र में विकास हुआ है। ये निम्नानुसार हैं:

(i) समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाना।

(ii) स्पेक्ट्रम को साझा करने, स्पेक्ट्रम का व्यापार करने और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) को युक्तिसंगत बनाने जैसे स्पेक्ट्रम संबंधी सुधार।

(iii) स्पेक्ट्रम को साझा करने के लिए प्रोत्साहन देना।

(iv) खुली और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से पर्याप्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(v) सुरक्षा उपायों के अध्ययधीन आटोमेटिक रूट के अंतगर्त दूरसंचार क्षेत्र में 100 % प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए अनुमति।

(vi) मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) के शीघ्र अनुमोदन के लिए पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ।

(vii) भारतीय तार मार्गाधिकार नियमावली 2016 और दूरसंचार अवसंरचना के अधिक तीव्र और आसान रोल आउट के लिए समय-समय पर संशोधन नियम जारी करना।

(viii) दूरसंचार टावरों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन (एसएसीएफए) क्लीयरेंस के लिए स्थायी परामर्शदात्री समिति के लिए प्रक्रिया काफी आसान बन गई है।

इसके परिणामस्वरूप बेस ट्रांस-रिसीवर स्टेशन (बीटीएस) की संख्या मार्च, 2014 में 6.49 लाख से बढ़कर मार्च, 2023 में 25.42 लाख हो गई है। इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या

मार्च, 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर सितबंर, 2023 में लगभग 91.82 करोड़ हो गई है। डेटा की लागत मार्च 2014 में 269 रूपए प्रति गीगाबाईट (जीबी) से घटकर मार्च 2023 में 9.94 रुपए प्रति जीबी हो गई है। विश्व में भारत का 5जी सेवाओं का रोल आउट सबसे तेज देखा गया है और 738 जिलों में 3.99 लाख बेस ट्रांस-रिसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए गए हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए मीडियन स्पीड भी मार्च 2014 में 1.30 मेगाबिट्स प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) से बढ़कर अक्टूबर, 2023 में 75.80 एमबीपीएस हो गई है।

(।।) उपर्युक्त के अतिरिक्त:

- भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध ढंग से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करके किया जा रहा है। दिनांक 13.11.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत कुल 2,07,346 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 04.08.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट के कार्य-क्षेत्र को ग्राम पंचायतों (जीपी) से आगे बढ़ाकर सभी बसे हुए गांवों तक करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम अनुमोदित कर दिया है।
- आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और सेवा से वंचित/सेवा की कम उपलब्धता वाले अन्य क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों की कनेक्टिविटी के लिए यूएसओएफ के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी), द्वीपसमूहों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना सहित विभिन्न परियोजनाओं और मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।
- देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 26,316 करोड़ रूपए की कुल लागत से देशभर के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं के सेचुरेशन के लिए परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए ''पूंजी निवेश 2022-23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम'' नामक स्कीम लॉन्च की है। ऑप्टिकल फाइबर केबल संबंधी पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई गई है और 24 राज्यों के संबंध में 2716 करोड़ रूपए की राशि की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन दिया गया है।
- देश के ग्रामीण/सुदूर/सेवा से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट सेवाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न यूएसओएफ परियोजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के दौरान 19,000 करोड़ रूपए संवितरित किए गए हैं।

- दिनांक 24-11-2023 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान के 33 जिलों सहित देश भर के 738 जिलों में 5जी मोबाइल नेटवर्क का रॉल आउट किया गया है। देश के लगभग 100 मिलियन मोबाइल उपभोक्ताओं ने 5जी सेवाओं का उपयोग करना आरंभ कर दिया है।
- अन्य विशेष प्रयासों में पर्याप्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता, स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार संबंधी सुधार, स्पेक्ट्रम सामंजस्यीकरण, मोबाइल टॉवर के लिए क्लीयरेंस से संबंधित सुधार, मार्गाधिकार अनुमति की प्रक्रिया में तेजी लाना, आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त वर्णित विभिन्न यूएसओएफ स्कीमों के अंतर्गत कवर किए जा रहे कुछ गांवों को छोड़कर देश के सभी राज्यों और जिलों में मोबाइल इंटरनेट कवरेज उपलब्ध है।

*****